क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

E-mail: krantisamay@gmail.com

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 145, मंगलवार, 19 जून 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कश्मीर समस्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार

जम्मू।

जम्मू कश्मीर की मौजूदा समस्या के लिए केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष केशव चन्द्र यादव ने कहा कि आतंरिक मसलों को हल करने में नाकाम यह सरकार संवेदनशील मामलों के समाधान के लिए भी विपक्ष की सलाह लेने में गुरेज करती है। श्री यादव ने सोमवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार देश को खतरे में बताकर सत्ता में दुबारा आने के लिए कश्मीर में युद्ध जैसे हालात दिखा रही है। केन्द्र ने सीमाओ को सुरक्षित किए घाटी में बिना एक तरफा सीजफायर कर दिया जिसके कारण ईद के मौके पर कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराये गए। केन्द्र की गलत रणनीति के चलते घाटी में हालात नहीं सुलझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है केन्द्र सरकार की न केवल विदेश नीति फेल है बल्कि आंतरिक नीति भी फेल है। एक सिर के बदले दस सिर लाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के शासन में रोज जवानों की हत्या हो रही है। जब केन्द्र सरकार से कश्मीर की समस्या नही सुलझ रही है तो इस मामले में उसे सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए थी लेकिन वर्तमान में भाजपा अपने खास तीन चार लोगों को छोड़कर किसी की बात सुनने को तैयार नही है ऐसे में विपक्ष की बात सुनने का उसके पास सवाल कहां उठता है। कांग्रेसी नेता ने कहा कि सविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। संघ लोकसेवा आयोग से चुने लोगों को दरकिनार कर संघ के लोगों को आगे लाया जा रहा है। वर्ग संघर्ष पैदा किया जा रहा है। विरोध करने वालों को किसी न किसी मामले फंसाया जा रहा है यह एक प्रकार से अघोषित आपातकाल ही है। उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट से ही कराया जाना चाहिए। जनता भी यही चाहती है। उन्होने दावा किया कि समान विचारधारा वाले दल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

शहीद औरंगजेब के परिवार से मिले आर्मी चीफ रावत, पिता बोले-बेटे की मौत का चाहिए बदला

जम्मू। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में शहीद हुए सिपाही औरंगजेब के परिवार से आज मुलाकात की। औरंगजेब को पुलवामा से 14 जून को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। उनका गोलियों से छलनी शव उसी शाम श्रीनगर से बरामद किया गया था। रक्षा सूत्रों ने बताया कि जनरल रावत ने शहीद के परिवार से मुलाकात करके उसे श्रद्धांजलि दी। शहीद सिपाही के पिता ने 32 घंटों के भीतर अपने बेटे की मौत का बदला लेने और सेना से आतंकवादियों को खत्म करने की अपील की। सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब को बीते दिनों अगवा किया गया था, जिसके बाद आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। आतंकियों ने उस वक्त औरंगजेब का अपहरण किया, जब वह ईद की छुट्टी लेकर अपने घर पुंछ लौट रहे थे। औरंगजेब उस कमांडो ग्रुप का हिस्सा थे, जिसने हिज्बुल कमांडर समीर टाइगर को मार गिराया था। 16 जून को उन्हें अंतिम विदाई दी गई थी।

घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑलआउट फिर शुरू, सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर

श्रीनगर। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में सीजफायर खत्म करने के ऐलान के साथ ही आज सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा में चार आतंकियों को ढेर कर दिया। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को बिजबेहारा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके बाद सुरक्षाबवों ने पूरे इलाके को घेर लिया। रविवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एकतरफा सीजफायर विराम को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सीजफायर पर निर्णय रमजान तक ही था। उल्लेखनीय है कि 16 मई को केंद्र ने कश्मीर में रमजान के महीने में शांति की पहल को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन को निलंबित रखने का आदेश दिया था लेकिन आतंकियों और पाकिस्तान दोनों ने भारत की नरम दिली का फायदा उठाया। आतंकियों ने राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी को गोलियों से छलनी कर दिया और दूसरी तरफ सेना के जवान औरंगजेब को अगवा कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। रमजान के दौरान भी आतंकियों ने भारतीय सेना पर कई हमले किए।

नकवी का केजरीवाल पर तंज, बोले-सीएम काम करने में जीरो और धरना देने में हीरो

नई दिल्ली। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज आठवें दिन भी उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर पर भूख हड़ताल जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भूख हड़ताल पर बैठ केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सीएम काम करने में जीरो और धरना देने में हीरो हैं। नकवी ने तंज कसते हुए कहा कि काम करने में जीरो, धरना में हीरो, करना कुछ नहीं, धरना सब कुछ, यही इनकी मानसिकता है। उन्होंने कहा कि आप नेता अब दिल्ली की जनता का विश्वास खो चुके हैं। बता दें कि 6 दिन अनशन पर बैठे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत रविवार रात बिगड़ गई जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जैन का किटोन लेवल बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें सांस लेने और पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी, अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।

ममता ने राहुल से बनाई दूरी, दीदी का मूड भांपने में जुटी कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार दूरी बनाए रखने से उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर चिंतित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का एक मजबूत मंच बनाने की कांग्रेस की मुहिम को ममता बार-बार झटका दे रही हैं। कांग्रेस से उनकी लगातार एक दूरी दिख रही है, जबकि विपक्ष के कई दलों के साथ मिलकर वे थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम चला रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं को ममता बनर्जी का मूड भांपने के लिए लगाया गया है। अगले कुछ दिनों में ये नेता ममता बनर्जी से मिल सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि दो दिनों के लिए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली आई ममता बनर्जी से इसी दौरान ही कांग्रेस के कुछ सीनियर मुलाकात कर सकते हैं। एक नाम अहमद पटेल का आ रहा है, जो सोनिया गांधी की ओर से ममता से मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात विपक्षी एकजुटता पर चर्चा के लिए होगी। दरअसल, ममता बनर्जी की कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से आत्मीयता सर्वविदित है। सोनिया से मिलने में ममता कोई हिचक भी नहीं महसूस करतीं, लेकिन जहां राहुल गांधी का नाम आता है, ममता छिटक कर एक किनारे हो जाती हैं। कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी ममता और सोनिया की नजदीकी देखने को मिली थी। लेकिन राहुल से वे कटी-कटी सी दिखीं। बीते दिनों राहुल गांधी की ओर से दी गई इफ्तार पार्टी में भी ममता नहीं पहुंचीं। हालांकि उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज रखा था। ममता विपक्षी एकजुटता के लिए अलग से थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में लगी हैं। वे जहां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में भेंट कर चुकी हैं, वहीं शरद पवार, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी जैसे प्रमुख नेताओं से भी बातचीत कर चुकी हैं। ममता की इस कोशिश के चलते कांग्रेस की विपक्ष की एकजुटता की मुहिम पर असर पड़ रहा है। विपक्ष के कई दल असमंजस की स्थिति में हैं।

सत्येंद्र जैन के बाद बिगड़ी मनीष सिसोदिया की तबीयत

नई दिल्ली।

उपराज्यपाल के दफ्तर में अनशन कर रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तबीयत भी बिगड़ गई है। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्येंद्र जैन के बाद अब सिसोदिया को भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। मनीष सिसोदिया की जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि कभी भी स्थिति गंभीर हो सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, मनीष सिसोदिया के कीटोन का स्तर 7.4 पर पहुंच गया है। कल यह 6.4 था जबकि यह स्तर शून्य होना चाहिए।

इसका स्तर दो से अधिक बढना घातक माना जाता है। सिसोदिया से कुछ घंटे पहले कल देर रात उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्येंद्र जैन को भी हालत बिगडने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है। सिसोदिया और जैन 11 जून से राजनिवास में मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री गोपाल राय के साथ धरने पर है।

कुमारस्वामी के मिलने पर बोले राहुल गांधी: सरकार चलाने में रहेगा कांग्रेस का पूरा सहयोग

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनको जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, ''करीब एक घंटे की मुलाकात के दौरान गांधी ने कुमारस्वामी से कहा कि वह अच्छी तरह सरकार चलाएं और कांग्रेस का उनको पूरा सहयोग रहेगा।'' इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी के सी वेणुगोपाल और जद(एस) महासचिव दानिश अली ने कहा, ''राहुल गांधी का कल जन्मदिन है। आज कुमारस्वामी ने उनसे मुलाकात की और जन्मदिन की अग्रिम बधाई दी।'' गौरतलब है कि कुमारस्वामी नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे।

दिल्ली में हाई अलर्ट- जैश के आतंकी प्लंबर बनकर इन जगहों पर कर सकते हैं हमला

नई दिल्ली। दिल्ली में जैश के आतंकी प्लंबर का रूप धरकर आतंकी हमला कर सकता है। ये इनपुट खुफिया एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को दी है। सूचना के मुताबिक आतंकी खासकर किसी सरकारी इमारत को अपना निशाना बना सकते हैं। सूचना के बाद दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हर जगह पर चाक चौबंद बढ़ा दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी को सूचना मिली है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी इस वारदात को अंजाम देने के लिए दिल्ली आने वाले हैं। उनकी संख्या तीन से चार हो सकती है। खुफिया इकाइयों ने इस पर के अलर्ट में आतंकवादियों की संख्या और उनके संगठन तक का जिक्र किया है। इसलिए दिल्ली पुलिस सहित तमाम इसे काफी गंभीरता से ले रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी हमले को देखते हुए सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेज की एक टुकड़ी को तैयार रहने को बोला गया है। इसके अलावा आशंका है कि आतंकी ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आईजीआई एयरपोर्ट और विमानों के रास्ते में या फिर रनवे पर अगर कोई ड्रोन या इस तरह का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत उसे नष्ट करने का आदेश जारी किया गया है।

जूनियर अब नहीं करेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सेवा, केरल सरकार खत्म करेगी प्रथा

तिरुवनंतपुरम।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आज कहा कि राज्य में कनिष्ठ पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ अधिकारियों की व्यक्तिगत सेवा में लगाने की परिपाटी खत्म की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह आश्वासन यहां पिछले हफ्ते अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी की 27 वर्षीय एक बेटी क्षरा के पुलिस ड्राइवर के साथ कथित दुर्व्यवहार के आलोक में आया है। इस घटना की कड़ी आलोचना हुई थी। मुख्यमंत्री एडीजीपी सुदेश कुमार की बेटी स्निग्धा द्वारा पुलिस ड्राइवर गवास्कर पर कथित हमले के विषय पर कांग्रेस के सबरीनाथन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। सुदेश कुमार को बाद में सशस्त्र पुलिस बटालियन के प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। विजयन ने कहा कि शीर्ष अधिकारियों की सेवाओं में कनिष्ठ अधिकारियों की तैनाती राज्य में कई दशकों से चलन में है। यह ब्रिटिश शासन से हमें मिली अपमानजनक प्रथा है। यह एक गंभीर मुद्दा है। राज्य में इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन के नाम पर कोई मानवाधिकार उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा।

शिवसेना ने कहा, निर्मला सीतारमण सबसे कमजोर रक्षा मंत्री

मुंबई।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में आज निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और उन्हें सबसे कमजोर और निष्क्रिय रक्षा मंत्री बताया। मुखपत्र सामना में शिवसेना लिखा कि पूरे हिन्दुस्तान को सेना की क्षमता पर भरोसा है लेकिन इसका नेतृत्व कमजोर है। भाजपा की सहयोगी ने कहा कि पिछले काफी समय से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इसका सीधा-सा अर्थ है कि नेतृत्व की कमान कमजोर हाथों में है। बता दें कि कि पिछले कुछ समय से घाटी में आतंकियों की गतिलिधियां काफी बढ़ गई हैं। हाल ही में आतंकियों ने सेना के जवान औरंगजेब को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। ईद के मौके पर भी नमाज अदा करने के बाद कश्मीर में जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर पथराव भी किया।

तूतीकोरिन: स्टरलाइट कॉपर प्लांट से लीक हुआ सलफ्यूरिक एसिड, मचा हड़कंप

चेन्नई।

तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट वेदांता कंपनी के प्लांट में एसिड लीक होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सील किए हुए प्लांट में बने एक स्टोरेज टैंक से ऐसिड लीक हुआ है। तूतीकोरिन प्रशासन ने इसे साफ करने का काम शुरू कर दिया है। वहीं तूतीकोरिन से जिलाधिकारी संदीप नंदूरी ने कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही इस प्लांट को बंद करने को लेकर काफी बवाल हुआ था। तब पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद प्लांट को प्रशासन ने बंद कर दिया था। बीते महीने 29 मई को तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में लगे 4 लाख टन सालाना (एलटीपीए) वाले कॉपर स्मेल्टर प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के बावजूद प्लांट को बढ़ाने का काम चल रहा था। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे।

नजरिया: केजरीवाल न बनें उद्धव ठाकरे

मुंबई

मुख के बजाए मुखपत्र की राजनीति करने वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के सोमवासरीय अंक में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। बकौल शिवसेना भारतीय सेना का नेतृत्व इस समय कमजोर हाथों में है। इसलिए ही सरहद खासकर पाकिस्तान के साथ लगती सरहद पर अशांति और हमले बढे हैं। वैसे पाठकों को याद ही होगा कि पाक सरहद के सिवा शिवसेना किसी और देश के साथ लगती सरहद को लेकर ज्यादा चिंतित भी नहीं रहती। आखिर उसकी राजनीति का आधार ही हिन्दू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव है। खैर तो मुद्दा यह है कि क्या सच में निर्मला सीतारमण एक कमजोर रक्षामंत्री हैं ? इंदिरा गांधी के बाद पहली बार रक्षामंत्रालय किसी महिला के हाथों में है। ऐसे में बीजेपी ने निर्मला के बहाने नारी स शक्तिकरण की जो नई परिभाषा गढ़ी थी क्या वो खोखली निकली? या फिर उसका एक नाराज पुराना साथी महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे ब्यान अपने मुखपत्र में छाप रहा है ? यह सवाल भी खंगालना होगा। और जब यह काम किया जाए तो यह जांचना भी जरूरी होगा कि उनके पूर्ववर्ती कितने सक्षम थे। शुरुआत पहले रक्षामंत्री बलदेव सिंह से कर लीजिये और वहां से होते हुए जगजीवन राम , यशवंत च्वहाण, मुलायम सिंह, शारद पवार और प्रणब मुखर्जी तक सबको खंगालना होगा तभी जाकर यह तय हो पाएगा कि सक्षम और कमजोर की परिधि और परिभाषा का आधार और दायरा क्या है। इस बीच इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव ,वीपी सिंह और चंद्र शेखर समेत पांच प्रधानमंत्रियों के पास भी रक्षा मंत्रालय रहा उस दौर को भी वांचना होगा। वास्तव में इंदिरा गांधी के दौर के बाद कोई भी रक्षामंत्री उतना प्रभावी नहीं रहा है जितना शिवसेना के आदर्श मापदंड ब्यान करते हैं। वजह यही रही कि हमारे देश में रक्षामंत्री का दर्जा गृहमंत्री के बाद आता है। युद्ध जैसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री के बाद रक्षामंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री ज्यादा अहम भूमिका में रहता है। इस सूची में आप सरदार पटेल, शास्त्री जी से लेकर राजनाथ सिंह तक का जिक्र कर सकते हैं। इंदिरा गांधी भी अगर प्रभावी थीं तो इसलिए की वे प्रधानमंत्री पद के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी संभाल रही थी। मौजूदा दौर को ही ले लें तो मोदी सरकार में ही तीन रक्षामंत्री हो चुके हैं। मनोहर परिकर के बाद अरुण जेटली ने भी यह पद संभाला। उधर गृहमंत्री के पद पर राजनाथ सिंह जैसे दबंग सियासतदान आसीन हैं। जाहिर है ऐसे में शिवसेना ने अगर घाटी की हिंसा और हालात का बहाना बनाकर निर्मला पर निशाना साधा है तो उसने मजह एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढा है। यह जाहिर करता है कि शिवसेना या उद्धव ठाकरे को घाटी में शांति बहाली की नहीं अपनी राजनीती चमकाने की चिंता ज्यादा है। कायदे से यह हमला राजनाथ सिंह पर होता तो मजा आता। लेकिन शिवसेना को पता है कि राजनाथ सिंह पलटवार भी करेंगे , लिहाजा उसने चालाकी से काम लिया। दरअसल ऐसी ही चालाकियों की वजह से शिवसेना ने लगातार अपना आधार खोया है। जनता अब महज सस्ती लोकप्रियता पाने की सियासत को बेहतर भांपने लगी है। इसलिए उसने गंभीर मुद्दों पर अपरिपक्व राजनीति करने वाले दलों को उनकी जगह दिखाई है। शिवसेना के लिए बेहतर होगा कि वह बीजेपी से अलग अपने वजूद की तलाश में गंभीर मुद्दों पर चर्चा करे ताकि जनता उसके प्रति संजीदा हो। अगर घाटी की हिंसा के बजाए शिव सेना ने गोवा में बिना सीएम के चल रही सरकार या केंद्र में बिना वित्त मंत्री के चल रहे मंत्रालय का मसला उठाया होता तो वह कहीं ज्यादा कारगर प्रहार होता।

संपादकिय

पर्यावरण की अनदेखी का गुबार

पिछले कुछ दिनों दिल्ली एनसीआर सहित देश के तमाम हिस्सों में धूल का गुबार छाया रहा। इसके चलते सांस लेना भी दूभर हो गया था। हालांकि बीते एक दो दिन से इससे कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन यह परेशानी कभी भी दोबारा दस्तक दे सकती है। असल में यह सब धरती के बढ़ते तापक्रम की ही देन है। एक बात तो साफ समझ आ ही गई है कि चाहे यह पाकिस्तान के सिंध में बढ़ते तापक्रम से जुड़ी हो या फिर ईरान से, कोई भी इसके असर से नहीं बच पाएगा। इसे अब दुनिया की बड़ी समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। पहले मिट्टी फिर पानी और अब तूफानी हवाओं ने भी साफ कर दिया कि बिगड़ते पर्यावरण पर हमारा न तो कोई नियंत्रण है और न ही इससे निपटने की कोई गंभीर कोशिश या चिंता नजर आती है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्लूएचओ की ताजा रपट ही हमारे नकारापन का खुलासा करती है। मोटे रूप में यह मान लेना चाहिए कि हमने सारी सीमाएं पार कर ली हैं और खुद को एक बड़े संकट में डाल दिया है। फिलहाल इस धूल ने ही अपना आतंक फैला रखा है। इस नए पर्यावरणीय प्रकोप ने अभी तक लगभग 125 लोगों की जान ले ली है और तमाम लोग इसके चलते सेहत संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई राज्यों में इसका असर देखा गया है। केवल दिल्ली एनसीआर ही इसकी चपेट में नहीं हैं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र से लेकर उत्तर व दक्षणि भारत सभी ने प्रदूषित पर्यावरण का नया रूप देखा है। हालात यह हैं कि पीएम 2.5 का स्तर सभी जगह काफी ऊंचा है। यह धूल किसी एक बारिश से हटने वाली भी नहीं है, बल्कि इसके फिर से दस्तक देने की आशंकाएं बनी हुई हैं। यही नहीं अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो धूल का यह गुबार ग्लेशियरों यानी हिमनदों को भी अपनी जद में ले लेगा। पहले से ब्लैक कार्बन की मार डोल रहे हिमनदों के लिए यह एक नया खतरा भी पैदा कर रहा है। एक आसान सी बात है जिसे शायद हम समझना ही नहीं चाहते कि हवा प्राण वायु है। इसके चलते ही हम सबकी सांसें और जीवन टिका हुआ है। वक्त के साथ सुविधाओं और विलासिताओं ने हम पर ऐसा असर किया है कि हम इसकी लगातार अनदेखी कर रहे हैं जिससे हम अपने ही बुने संकट के जाल में फंसते जा रहे हैं। लगभग हर वर्ष 70 लाख लोग दुनिया में वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया की 90 फीसदी आबादी प्रदूषण के घेरे में फंस चुकी है। अब इस नए तूफानी जंजाल के क्या-क्या प्रतिकूल असर होंगे यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण पूर्वी एशिया व दक्षणि एशिया में ही है जिनमें भारत व चीन जैसे देश है। यहां वायु में जहरीले तत्व शेष विश्व की तुलना में पांच गुना ज्यादा हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के अनुसार अगर हम आज वायु प्रदूषण के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो कभी भी सही और सतत विकास में खरे नहीं उतर सकते। अब इंग्लैंड में देखिए जहां हर वर्ष वायु प्रदूषण से 40,000 लोगों की जान तो जा ही रही है, वहीं हर साल 20 अरब पाउंड का नुकसान भी उठाना पड़ा रहा है। यहां के कानून ने इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति करार दिया है।।1विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट के अनुसार वाराणसी, आगरा और कानपुर जैसे शहरों में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा है। इन तीनों शहरों से कुछ खास बातें भी जुड़ी हैं। मसलन वाराणसी देश के प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है। आगरा का ताजमहल विश्वप्रसिद्ध है और कानपुर पहले ही गंगा को टेनरी उद्योगों के कारण बर्बाद करने के लिए कुख्यात हो गया है। सच तो यह है कि ये 14 शहर जो इस सूची में आए हैं केवल यही प्रदूषित नहीं हैं, बल्कि भारत में लगभग सभी शहरों की कमोबेश यही कहानी है। वायु प्रदूषण मानक के अनुसार पीएम 85 के आसपास ही बर्दाश्त की सीमा है। दूरदराज के केवल वही इलाके इसकी जद से बचे होंगे जहां जहां गाड़ियों और उद्योगों की भरमार नहीं है, वरना देश का कोई भी कोना वायु प्रदूषण से अछूता नहीं है। बहरहाल अब इस नए तूफानी संकट ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। इस धुंध और वायु प्रदूषण को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। यह धीमे जहर की तरह कार्य करता है। इसमें सल्फेट लेड कार्बन नाइट्रेट आदि होते हैं जो सीधे सीधे हृदय, फेफड़ों में कैंसर, न्यूमोनिया आदि बीमारियों की वजह माने जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार भी निम्न एवं मध्यम आमदनी वाले वर्ग पर ही पड़ती है।

कश्मीर: सीज़फायर बना 'आतंकियों की ईद' ?

बड़े आश्चर्य की बात है कि अफगानिस्तान, सीरिया, इराक तथा यमन जैसे देशों की हालत देखने के बावजूद मुट्ठी भर आतंकवादी तथा उनको भड़काने वाले चंद स्वार्थी अलगाववादी नेता यह नहीं समझ पाते कि यदि भारतीय सेना द्वारा भी आतंकियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई एकतरफा तरीके से की गई, ऐसे में वहां के आम आदमियों को कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है।

तनवीर जाफरी

पिछले महीने जम्मू-कश्मीर राज्य की पीडीपी-भाजपा संयुक्त सरकार की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा माह-ए-रमज़ान शुरु होने से पहले राज्य में भारतीय सेना द्वारा एकतरफा सीज़फायर करने के अनुरोध किया गया था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार तो ज़रूर कर लिया परंतु देश व कश्मीरवासियों को इस सीज़फायर की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। क्या राज्य की जिस आम जनता की आज़ादी, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता उनकी शांति तथा रमज़ान के दौरान दिन-रात की जाने वाली इबादतों के मद्देनज़र भारत सरकार द्वारा सेना को इस पवित्र महीने में आतंकियों के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई न करने का जो निर्देश 'सीज़फायर' के रूप में दिया गया था सरकार को इसके सकारात्मक परिणाम मिले भी हैं? या फिर यह एकतरफा सीज़फायर की कवायद कश्मीरवासियों के लिए तथा भारतीय सेना के लिए एक घाटे का सौदा साबित हुई जबकि आतंकियों द्वारा इस इकतरफा सीज़फायर का इकतरफा फायदा उठाया गया और यह 'आतंकियों की ईद' ही साबित हुआ? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी इसी प्रकार का एक प्रयोग कश्मीर में किया गया था। परंतु उस समय भी आतंकी अपनी हिंसापूर्ण कार्रवाईयों से बाज़ नहीं आए थे। इस बार भी पवित्र रमज़ान में जहां भारतीय सेना ने तथा राज्य व केंद्र की सरकार ने सामूहिक रूप से आतंकवादियों के प्रति नरमी बरतने का जो सद्भावपूर्ण फैसला किया आतंकियों ने संभवत: उसे सेना व सरकार की कमज़ोर समझा और अपनी नापाक हरकतों को रमज़ान के लगभग पूरे महीने जारी रखा। कश्मीरी अलगाववादियों व आतंकवादियों की इस कार्रवाई में सीमापार से पाकिस्तान की ओर से भी भरपूर मदद की जा रही थी। नतीजतन पूरे महीने में घुसपैठ की कई घटनाएं घटीं, पाकिस्तान द्वारा सीमा पर कई बार गोलीबारी की गई, सीमावर्ती गांवों के रहने वाले सैकड़ों लोगों को रमज़ान में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई भारतीय जवान शहीद हुए और कई बेगुनाह नागरिकों की जानें गईं। आ?खिरकार रमज़ान के महीने का समापन कश्मीर घाटी के एक वरिष्ठ, प्रसिद्ध व निष्पक्ष पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के साथ हुआ। शुजात बुखारी के साथ आतंकवादियों ने उनके सहयोगी दो पुलिस कर्मियों की भी हत्या कर दी। सवाल यह है कि एक ओर तो जहां इसी ईद के दौरान दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन समझे जाने वाले तालिबानों ने अफ्गानिस्तान में चल रहे इसी प्रकार के संघर्ष विराम को सम्मान देते हुए वहां ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से संघर्ष विराम की समय सीमा को और अधिक बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी है तथा तालिबानों से भी राष्ट्रपति ने ऐसी ही अपील की है। अफगानिस्तान सरकार द्वारा कई तालिबानी आतंकियों को वहां की जेलों से भी रिहा कर दिया गया है। और तो और गत दिवस मनाई गई ईद में अफगान सैनिक व तालिबानी आतंकी जो कभी एक-दूसरे के खून के प्यासे दिखाई देते थे वही एक-दूसरे से गले मिलते हुए और ईद की मुबारकबाद का आदान-प्रदान करते हुए देखे गए। वहीं आखिर भारतवर्ष की कश्मीर समस्या या कश्मीर में फैला आतंकवाद क्या तालिबानी आतंकी विचारधारा से भी ज्यादा खतरनाक रूप धारण कर चुका है? बड़े आश्चर्य की बात है कि अफगानिस्तान, सीरिया, इराक तथा यमन जैसे देशों की हालत देखने के बावजूद मुट्ठी भर आतंकवादी तथा उनको भड़काने वाले चंद स्वार्थी अलगाववादी नेता यह नहीं समझ पाते कि यदि भारतीय सेना द्वारा भी आतंकियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई एकतरफा तरीके से की गई, ऐसे में वहां के आम आदमियों को कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि दमनात्मक सैनिक कार्रवाई का कश्मीर के सौंदर्य वहां के पर्यट्न तथा आम लोगों के जनजीवन, शिक्षा स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वे यह भी नहीं समझ पाते की उन्हें भड़काने तथा उकसाने वाला उनका कथित शुभचिंतक पाकिस्तान स्वयं अपने ही देश में किस प्रकार से आतंकवाद का शिकार है? कई राजनैतिक विश्लेषक इस बात का संदेह जता चुके हैं कि पाकिस्तान अपने अंतर्विरोधों के चलते तथा वहां के अनेक सत्ता केंद्र होने के नाते लगभग बिखरने की कगार पर खड़ा हुआ है और इन्हीं अलग-अलग सत्ता केंद्रों ने पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद को फलने-फूलने का ऐसा मौका उपलब्ध कराया है जिससे पाकिस्तान को पूरी दुनिया आतंकवाद के एक बड़े उत्पादक देश के रूप में देख रही है। क्या ऐसा पाकिस्तान इन कश्मीरी अलगाववादियों व आतंकवादियों की किसी प्रकार की दूरगामी सहायता कर पाने की स्थिति में है? सिवाय इसके कि धर्म के नाम पर कश्मीर के बेरोज़गार, गरीब युवाओं को वरगलाता रहे। पत्रकार शुजात बुखारी निश्चित रूप से ऐसे पत्रकार नहीं थे जो कश्मीर की अवाम का पक्ष न रखते हों। या फिर कश्मीर में होने वाली सैन्य ज़्यादतियों पर आंखें बंद रखते हों। वे वास्तव में एक निष्पक्ष व निडर पत्रकार थे जो अपने पेशे को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देना बखूबी जानते थे और दे रहे थे। एक पत्रकार के रूप में कश्मीर में उनकी कितनी लोकप्रियता थी और उनकी शहादत के बाद कश्मीर की अवाम ने उसे किस रूप में देखा यह बुखारी की उस शव यात्रा से स्वयं साबित हो जाता है जिसमें हज़ारों की भीड़ उनके जनाज़े में शरीक होकर उनकी मातमपुरसी कर रही थी। कौन कश्मीरी या कौन मुसलमान या कौन सा इंसान शुजात बुखारी की ईद से एक दिन पूर्व व रमज़ान के आखिरी रोज़े के इफ्तार के वक्त से चंद मिनट पहले होने वाली इस हत्या को जायज़ ठहराएगा? बुखारी को अगले ही दिन सुबह अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ जाकर ईद मनानी थी जहां उनकी शहादत की खबर सुनने के बाद ईद का दिन मातम में बदल गया। शुजात बुखारी के परिजनों तथा कश्मीर के शांतिप्रिय लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कश्मीर में सेना द्वारा रमज़ान में घोषित किए गए संघर्ष विराम का इतना बड़ा खमियाज़ा कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ेगा।

कहा जा सकता है कि जहां भारत सरकार ने राज्य सरकार के एकतरफा सीज़फायर करने के निवेदन को स्वीकार कर अपनी ओर से यह दर्शाने की कोशिश की कि भारत सरकार कश्मीर में शांति बहाली के लिए हर प्रकार के ज़ोखिम उठाने को तैयार है और निश्चित रूप से सरकार को अपने इस फैसले का खमियाज़ा भी भुगतना पड़ा है वहीं यह भी साफ हो गया कि आतंक की राह पर चलने वाले लोग न तो रमज़ान की पाकीज़गी को समझने की क्षमता रखते हैं न ही उन्हें अल्लाह, इस्लाम तथा धार्मिक शिक्षाओं की कोई परवाह है। संभवत: सेना द्वारा सीज़फायर के रूप में उनके प्रति बरती गई नरमी आतंकवादियों के लिए तो ईद साबित हुई जबकि रमज़ान के महीने में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों, राज्य के पुलिस कर्मियों, शुजात बुखारी के परिजनों तथा रमज़ान में मारे गए बेगुनाह लोगों के परिवार के लोगों के लिए यह महीना मोहर्रम जैसे किसी शोकपूर्ण महीने से कम नहीं रहा। लिहाज़ा सरकार को आतंकवाद का जवाब उसी की भाषा में दो गुणा व चार गुणा ताकत से देने की ज़रूरत है। कश्मीर में शांति स्थापित करने का पहला ज़िम्मा वहां सक्रिय आतंकवादियों, अलगाववादी नेताओं तथा पाकिस्तान के बहकावे में आने वाले लोगों का होना चाहिए ।

वक्त के साथ गिरती झूठ की दीवार

असत्य की उम्र नहीं होती, लेकिन प्रायोजित झूठ की बात दूसरी है। यह प्रायोजकों के बुद्धि कौशल से चर्चा में बना रहता है। राष्ट्रीय पमानजनक सत्य शूल की तरह हृदय में चुभते हैं। आर्य हमारे पूर्वज हैं। वे वैदिक संस्कृति, सभ्यता और दर्शन के जन्मदाता हैं। दुनिया के प्राचीनतम ज्ञानकोश ऋग्वेद के द्रष्टा रचयिता हैं बावजूद इसके उन्हें विदेशी हमलावर बताया-पढ़ाया जाता है। डॉ. आंबेडकर ने 'हू वेयर शूद्राज' लिखकर आयी के विदेशी होने का सिद्धांत गलत ठहराया। मार्क??सवादी चिंतक डॉ. रामविलास शर्मा और संस्कृति दर्शन के विद्वान डॉ. भगवान सिंह आदि ने भी इस झूठ का पर्दाफाश किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान को पमानित करने की योजना से आर्य आक्रमण का महाझूठ ब भी जारी है। राखीगढ़ी-हरियाणा और ग्राम सिनौली जिला बागपत उत्तर प्रदेश से शुभ सूचनाएं आई हैं। सिनौली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोदाई में ईसा पूर्व 2000-1800 के समय का ताम्र मोतियों से सजा रथ, कटार और तलवार के साथ आभूषण भी मिले हैं। वहीं राखीगढ़ी में 5000 वर्ष पुराने नरकंकाल के डीएनए परीक्षण ने चौंकाया है। दोनो ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता और निरंतरता को सही ठहराया है।।1भारत प्राचीन सभ्यता है। दोनों ध्ययनों ने प्राचीन ऋग्वैदिक सभ्यता को देसी पाया है। डेकन कॉलेज पुणो के कुलपति बसंत शिंदे व बीरबल साहनी प्रयोगशाला लखनऊ के प्रमुख नीरज के नेतृत्व में हुए डीएनए विश्लेषण के नुसार शव संस्कार की पद्धति ऋग्वैदिक काल से मिलती जुलती है। कंकाल परीक्षण में उच्चतर स्वास्थ्य पाया गया है। ज्ञान तंत्र भी वैदिक काल का नुसरण करने वाला है। बर्तन और ईंटों का उपयोग भी वैदिक सभ्यता की निरंतरता बताता है। आयी पर हड़प्पा सभ्यता नष्ट करने के आरोप हैं। हड़प्पा को प्राचीन और ऋग्वैदिक सभ्यता को परवर्ती सिद्ध करने की कसरत भी पुरानी है। भारत रत्न पीवी काणो ने 'धर्मशास्त्र के इतिहास' में वैदिक संहिताओं का काल 4000-1000 ईसा पूर्व तक बताया है। ऋग्वेद का कुछ भाग पांच हजार साल से भी पुराना है। थर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता 4 हजार ईसा पूर्व के आसपास हो सकते हैं। भारत के लोग उस समय भी रथारूढ़ थे। रथ का उपयोग ऋग्वेद के रचनाकाल से भी प्राचीन है। घोड़े उन्हें खींचते थे। घोड़े विदेशी नहीं भारतीय आर्य संपदा थे। मैक्डनल और कीथ ने 'वैदिक इंडेक्स' (खण्ड 1) में लिखा है, 'सिंधु और सरस्वती तट के घोड़े, मूल्यवान थे।' 1ऋग्वेद में घोड़े के तमाम मंत्र हैं। ऋषि इंद्र को श्वपति कहते हैं और पने लिए घोड़ा मांगते हैं। एक न्य मंत्र में वह घोड़े के साथ जौ भी मांगते हैं। एक मंत्र में च्छा घोड़ा रथ के आगे-आगे चलता है। घोड़ा समृद्धि और गति का प्रतीक है। रथ निजी यात्र के उपकरण थे और युद्ध के भी। ऋग्वेद में घोड़ा और रथ की सफाई के भी उल्लेख हैं। घोड़ा और रथ भारत के मन की सुंदर भिलाषा हैं। उपनिषद दर्शन ग्रंथ हैं, लेकिन दर्शन बोध में इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम। सूर्य भी रथ पर चलते हैं। उसे सात घोड़े खींचते हैं। काल नुभूति है पदार्थ नहीं। काल भी रथ पर चलते हैं। थर्ववेद के कालसूक्त में 'ज्ञानी ही कालरथ पर बैठ सकते हैं।' जिसके पास रथ वही श्रेष्ठ संपन्न। ऋग्वेद में सिंधु नदी के बहाव की तीव्रता को घोड़ी की गति की उपमा दी गई है। वैदिक पूर्वज घोड़ों को खेती में प्रयोग नहीं करते थे। यूरोप में घोड़े खेती के काम भी आते थे। रथ सुमेरी सभ्यता में भी थे, परंतु उनके पहियों में आरे नहीं थे। भारतीय रथों में आरे थे। वे हल्के थे। बागपत में मिला दो हजार साल पुराना रथ भारत के प्राचीन वैभव और वैदिक सभ्यता का मुख्य साक्ष्य है। 1भारत के मुठ्ठी भर स्वयंभू विद्वान ही आयी को विदेशी बताते रहे हैं। 1922 तक सिंधु सभ्यता की जानकारी नहीं थी। विलियम जोंस ने 'रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल' (1786) में संस्कृत को ग्रीक और लैटिन से भी समृद्ध भाषा बताया था, लेकिन संस्कृत को किसी न्य भाषा का विकास बताया। दुनिया की सर्वाधिक विकसित संस्कृत भाषा सामने थी, लेकिन संस्कृत को मूल भाषा मानने से यूरोपीय नस्लवाद को कष्ट होता इसलिए दूसरी भाषा की चर्चा जरूरी थी। इसी कल्पित भाषा का नाम इंडो यूरोपियन चल निकला। इसे बोलने वाले जनसमूह और भाषा के मूल स्थान की समस्या पेचीदा थी। आयी की मूल भूमि भारत से बाहर बताने के लिए जर्मनी, हंगरी, साइबेरिया, ओल्गा नदी क्षेत्र, पामीर और एशिया माइनर तक दिमाग दौड़ाया गया। वे सिद्ध करना चाहते थे कि ज्ञात क्षेत्र के निवासी आयी ने ईरान के रास्ते आकर भारत पर आक्रमण किया। जोंस की बातें सुविधाजनक थीं। कथित इंडो यूरोपीय भाषा के आधार पर इंडो यूरोपीय नस्ल की कल्पना की गई। इसी फर्जीवाड़े का शिकार बने भारतीय आर्य।।1भारत सरकार को कराची-लाहौर के मध्य रेलवे के लिए ईंटें चाहिए थीं। 1922 की हड़प्पा खोदाई में एक नगर मिला। भारतीय पुरातत्व विभाग ने और खोदाई की। सिंधु सभ्यता का पता चला। यहां से लगभग 600 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो था। 1925 में मैके ने मोहनजोदड़ो से लगभग 100 किमी दूर बन्हुदार का उत्खनन कराया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चान्हुदारों से प्राप्त सामग्री पर सिंधु सभ्यता का विवेचन हुआ।

प्रलय को आमंत्रित करते लोग

एक बार महान संत से एक शिष्य से प्रश्न किया कि 'सुना है प्रलय बहुत बड़ी आफत होती है। प्रलय में सारे संसार को खत्म करने की ताकत है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रलय होता क्या है?' यह सुनकर शिष्य को संत ने जवाब दिया कि 'तुम्हारा कहना सही है कि प्रलय बहुत बड़ी बला होती है। देखते हैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब दे सकता है क्या, यह कहकर उन्होनें दूसरे शिष्यों की ओर देखा।'

तभी एक अन्य शिष्य ने कहा, 'मेरी नजर में खुदा के प्रति इंसान के अपराध ही प्रलय की वजह है।' एक अन्य शिष्य रे ने कहा, 'जब इंसान के जुल्मों को धरती झेल नहीं पाती है तो खुदा प्रलय के जरिए इसको धोता है।' एक अन्य शिष्य उठा और उसने कहा, 'कमजोर और गरीब इंसान के आंसू का एक कतरा ही प्रलय की असली वजह होती है।' महान संत सभी शिष्यों की बातें गौर से सुन रहे थे, अंत में उन्होंने कहा कि 'यह सही है कि कमजोर व गरीब इंसान की आंखों से निकलने वाले आंसू की एक बूंद ही प्रलय की वजह है। इसलिए किसी भी कमजोर आदमी के दुख-दर्द यदि हम दूर नहीं कर सकते हैं तो उसको किसी भी तरह की तकलीफ तो देनी ही नहीं चाहिए। निसहाय इंसान इतना लाचार होता है कि वह कष्टों को सिर्फ सहन कर सकता है उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता है वह। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है इसलिए उनकी लाचारी उनका दुख उनकी आंखों से आंसूओं के जरिए निकलता है। इसलिए गरीबों पर रहम करोगे तो खुदा भी तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात को समझते नहीं है और प्रलय को आमंत्रित करते रहते हैं।'

चिंतन मनन

कश्मीर और विदेशों से मिल रही चुनौतियों से मोदी सरकार की लोकप्रियता घटी

- सनत जैन

नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिस चमत्कारिक छवि के साथ प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी। उन्होंने देश और विदेश में जो विश्वास और उत्साह मतदाताओं और दुनिया के देशों में जगाया था। लोग यह मान कर चल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा हैं। पिछले 2 साल से जिस तरह की चुनौतियां भारत को मिल रही है। उससे अब आम आदमी की विश्वास डगमगा गया है। चार लाख की आबादी वाले मालदीव की सरकार ने भारतीय लोगों की नौकरी खत्म करने की घोषणा की है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भारतीय लोगों के लिए एच1बी वीजा की शर्तों में जो परिवर्तन किया है उससे भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एच1बी वीजा होने के बाद भी वहां पति या पत्नी को नौकरी नहीं देने का प्रस्ताव किया है। एच-1 बी वीजा के लिए 60 हजार डॉलर आय की शर्त लगा दी है। इसी तरह अमेरिका ने भारत से निर्यात होने वाली सामग्री पर कस्टम की आयात ड्यूटी बढ़ा दी हैं। अमेरिका में भारत से जो निर्यात हो रहा था। अब उसमें अमेरिका द्वारा ड्यूटी बढ़ाने से निर्यात व्यापार में भारत को बड़ा नुकसान होगा। कहा जा रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते बहुत बेहतर हैं। इन रिश्तो के कारण भारत सरकार ने रूस से भी दूरियां बना ली थी। अमेरिका को भारत की जो सहायता करनी थी, वह तो अमेरिका कर नहीं रहा है। उल्टे ट्रंप ने जी-7 की बैठक में यह कहकर भारत की तौहीन कर दी कि अमेरिका के पास कोई गुल्लक नहीं है। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए हर किस्म से अमेरिका की चम्मच गिरी कर ली। 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश की अनुमति दे दी। खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को अनुमति देकर भी अमेरिका के साथ अपने बेहतर रिश्ते भारत सरकार नहीं बना पाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच कोई अंतर नहीं है। भारत सरकार अभी तक अमेरिका के साथ अपने रिश्तो को बराबरी पर नहीं ला पाई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने जरुर अमेरिकी राष्ट्रपति को झुकाने का काम किया है। इससे सारी दुनिया में किम जोंग की प्रशंसा हो रही है।

डोकलाम को लेकर चीन की कार्यवाही से भारत सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। प्रधानमंत्री के रुप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यक्तिगत संबंधों का बड़ा प्रचार प्रसार किया गया। किंतु चीन भी भारत के साथ वही सब कर रहा है जो अमेरिका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देश कर रहे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कश्मीर के मामले में भारत को मानव अधिकारों का उल्लंघन करने और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जाने की रिपोर्ट प्रकाशित करके भारत के मुंह में एक तमाचा मारने जैसा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका की शह पर भारत को बदनाम किया है। भारत की यह छबि स्थाई रूप से बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध में भारत की राय जानने का भी प्रयास नहीं किया। इसी तरह सीआईए की रिपोर्ट में संघ परिवार को हिंदूवादियों के लिए काम करने वाला संगठन बताया। वही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को धार्मिक लड़ाकू आतंकी संगठन बता दिया है। पहली बार अमेरिका ने भारत के आतंकी संगठनों की पहचान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शामिल किया है। इससे समझा जा सकता है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका की सरकार और डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच है।

कश्मीर एवं पाकिस्तान के मुद्दे पर 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन यूपीए सरकार को बहुत बुरी तरीके से घेरा था। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर अब स्थिति 2014 की तुलना में कई गुना खराब हुई है। हाल ही में श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों ने समाचार पत्र के संपादक शुजात बुखारी की सरेआम हत्या कर दी। सुरक्षाबलों द्वारा आतंकवादियों को ढूंढ-ढूंढ कर मारने के बाद भी रोजाना आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान भी नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी कर रहा है। जिसमें दर्जनों सैनिक और कश्मीरी नागरिक मारे गए है। भारतीय सुरक्षा बलों के अधिकारी और सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं। सैनिकों के शहीद होने के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो बड़े-बड़े दावे सरकार द्वारा किए गए थे। वह सारे दावे अब मोदी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। नीरव मोदी को लेकर जिस तरह भारत सरकार और जांच एजेंसियों ने पक्षपात का रुख अख्तियार किया है। उससे भारत सरकार की साख विदेशों में भी कम हुई है। मोदी सरकार की जांच एजेंसियों ने नीरव मोदी का पासपोर्ट तो रद्द कर दिया। किंतु इसकी सूचना दूसरे देशों को नहीं दी। जिसके कारण वह कई देशों में घूमता रहा। जिससे विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिला है।

देश में और विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमत्कारिक छवि बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जो प्रयास हुए। उसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी छवि के अनुसार अब भारत और विदेशों के लोग उन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन पिछले महीनों में और कई मायनों में जिस तरीके के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वह उनकी छवि के अनुकूल नहीं हैं। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान लगातार भारत की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। अमेरिका आर्थिक और सामरिक रूप से भारत का शोषण कर रहा है। वही चीन भारत की सभी सीमाओं पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इत्यादि सीमावर्ती देशों में अपनी पैठ बढ़ा कर भारत के लिए चुनौतियों को बढ़ा रहा है। इसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जो मोदी की चमत्कारी छवि से मेल खाता हो।

राशि भविष्य फल

मेष राशि – यात्रा व वृत्ति से लाभ, कुसंग से हानि, अपनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक समाचार की प्राप्ति।

वृष राशि – शुभ कार्य, भूमि से हानि, सिद्धी, विरोधी उलझाने की कोशिश करेंगे, कार्य बनेंगे।

मिथुन राशि – अधिक व्यय होगा, स्वजन कष्ट, विवाद, आर्थिक कमी का अनुभव होगा, धैर्य रखें।

कर्क राशि – हानि, रोगभय, नौकरी में कष्ट, चिन्ता, राजकार्य मामले–मुकदमे में संतोष होगा।

सिंह राशि – निराशा के बाद लाभ, शत्रु भय, कार्य में सफलता, आर्थिक सुधार होगा।

कन्या राशि – शरीर कष्ट, लाभ, राजभय, उद्योग–व्यापार में अड़ंगे आयेंगे, सावधानी से कार्य करें।

तुला राशि – चोट–अग्नि भय, धार्मिक कार्य, कष्ट, व्यर्थ व्यय होगा, अनाप–शनाप खर्च से परेशानी बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि – बाधा, उलझनें बढ़ेंगी, लाभ, यात्रा, कष्ट, गृह कार्य, राजकार्य में परेशानी अवश्य होगी।

धनु राशि – शत्रु भय, मुकदमे में जीत, रोगभय होगा, व्यापार में सुधार, कष्ट अवश्य ही होगा।

मकर राशि – व्यापार में लाभ, शत्रुभय, धन सुख, कार्य में सुधार होगा, परेशानियों से कष्ट का अनुभव होगा।

कुंभ राशि – कलह, व्यर्थ खर्च होगा, सफलता प्राप्त होगी, विरोधी असफल रहेंगे, व्यापार में सुधार होगा।

मीन राशि – स्वजन सुख, पुत्र चिन्ता, धन हानि, व्यापार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, धैर्य पूर्वक कार्य आगे बढ़ायें।

भारत को भी झेलने होंगे 'ट्रेड वार' के नुकसान

नई दिल्ली ● एजेंसी

वैश्विक कारोबारी मंच पर ट्रेड वार को लेकर जो आशंका थी वह सच साबित होने लगी है। ट्रंप प्रशासन ने मैक्सिको से होने वाले आयात पर टैक्स लगाने का जो सिलसिला शुरू किया था, उसके लपेटे में चीन और भारत भी आ चुके हैं। इसके जवाब में पहले चीन ने और अब भारत ने भी अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जानकारों की मानें तो दुनिया के बड़े देशों में कारोबारी हितों को लेकर खींचतान तेज हुई, तो यह सभी के लिए बुरी खबर होगी। भारत पर ब्याज दरों से लेकर शेयर बाजार तक पर इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष असर पड़ सकता है।

शेयर बाजार में उथल-पुथल की आशंका

अमेरिका की तरफ से चीन से 50 अरब डॉलर के आयात पर शुल्क लगाने और उसके जवाब में चीन की तरफ से अमेरिकी ऑटोमोबाइल, क्रूड व कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का एलान किया गया है। माना जा रहा है कि इससे अमेरिका में महंगाई बड़ेगी। अमेरिका का केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व बैंक) पहले ही ब्याज दरों को बढ़ाने का सिलसिला शुरू किए हुए है। इन कदमों के बाद ब्याज दरों में और तेज वृद्धि हो सकती है। जनवरी, 2018 के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से 24 करोड़ डॉलर की राशि बाहर निकाल चुके हैं। यह सिलसिला और तेज हो सकता है क्योंकि अमेरिका में संस्थागत निवेशकों को ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। इससे भारतीय शेयर बाजार में अनिश्चितता का माहौल देखा जा सकता है। देश के बांड्स बाजार से भी विदेशी संस्थागत निवेशक अपना निवेश खींच सकते हैं, जो सीधे तौर पर भारतीय बैंकों की कमाई पर असर डालेगा।

थम सकती है आर्थिक विकास की रफ्तार

पिछले दो महीनों में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अलावा हाल ही में आरबीआइ की मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा गया है कि ट्रेड वार हराने से दुनिया की आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। अप्रैल, 2018 में वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए आरबीआइ ने क्रूड की कीमत व ट्रेड वार को दो सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर चिन्हित किया था।

सेंसेक्स में मामूल गिरावट

नई दिल्ली (एजेंसी)। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स सोमवार को सौदों के मुकाबले 35,592 .36 पर था, जो 29 .78 अंक या 0 .08 फीसदी के नीचे था, जबकि निफ्टी 50 9 .55 अंक या 0 .0 9 फीसदी की हानि के साथ 10,808 .15 पर था। तकनीकी विशेषज्ञों ने कहा कि दलाल स्ट्रीट पर अनिश्चितता जारी रहेगी और बाजार में सुधार दिखाई दे सकता है। केआईएफएस ट्रेड कैपिटल के एवीपी-तकनीकी विश्लेषण, ज्ञानेश्वर पदवाल ने कहा, वर्तमान परिदृश्य में, निफ्टी सुधारात्मक पैटर्न में प्रकट हुआ है जहां बैल और भालू के बीच अनिश्चितता समेकन का गठन करती है। इंटरमीडिएट समर्थन 10,750 के स्तर के करीब और 10,900 के करीब प्रतिरोध होता है। इस बीच, एशियाई शेयर सोमवार को गिर गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीनी आयात पर टैरिफ के साथ आगे बढ़कर व्यापार तनाव को तोड़ दिया, जिससे बीजिंग को तुरंत जवाब देने के लिए प्रेरित किया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों की एमएससीआई की सबसे बड़ी सूचकांक 31 मई से 0 .4 फीसदी कम हो गई है।

रतन टाटा ने लांच किया एनईएसएफ बैंक

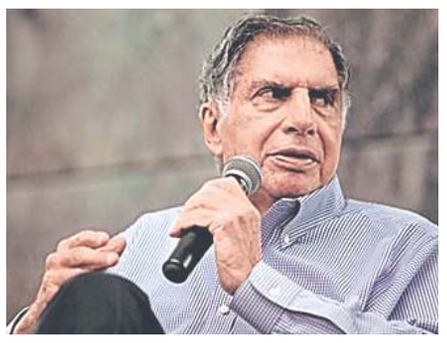

गुहाटी ● एजेंसी

टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने रविवार को असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के साथ रविवार को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस (एनईएसएफ) बैंक लांच किया। क्षेत्र के पहले स्मॉल बैंक की शुरुआत 28 शाखाओं के साथ की गई है। टाटा ने इस मौके पर कहा कि अगर देश को तेज गति से विकास करना है, तो हमें अवसर पैदा करने होंगे और उद्यमिता को ब?ावा देना होगा। गौरतलब है कि रतन टाटा ने आरएनटी एसोसिएट्स के माध्यम से बैंक में 40 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

टाटा ने कहा, भारत में विकास और समृद्धि का गवाह रहे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि कर्जदारों को विकास के लिए कर्ज मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन देश में ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जिन्हें या तो अपेक्षित मदद नहीं मिली है या जिनके लिए वित्तीय मदद बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। टाटा ट्रस्ट्स को अवसर और पूंजी से अब तक वंचित रहे लोगों में समृद्धि का वाहक बनने की बेहद खुशी है और मैं बैंक की हर तरफ से सफलता की कामना करता हूं। आरजीवीएन (नॉर्थ ईस्ट) माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड को पिछले वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष के आखिरी दिन स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने संबंधी लाइसेंस मिला था।

तेरह राज्यों के राजकोषीय घाटे में बड़ी गिरावट

मुंबई ● एजेंसी

पिछले वित्त वर्ष के दौरान खर्च में कमी के चलते 13 राज्यों का राजकोषीय घाटा औसतन 25 फीसद तक गिर गया है। घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी राजकोषीय घाटे से संबंधित प्रारंभिक आंकड़ों के हवाले से कहा है कि समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान इन राज्यों का राजस्व 7.5 फीसद ब?ने के बावजूद राजकोषीय घाटे में कमी दर्ज की गई है।

आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष (2016-17) में इन राज्यों का राजस्व 11.5 फीसद बड़ा था। एजेंसी ने कहा कि मार्च, 2017 के आखिर में इन 13 राज्यों का राजकोषीय घाटा 4.3 लाख करोड़ रुपये था, जो इस वर्ष मार्च के आखिर में 25.1 फीसद घटकर 3.2 लाख करो? रुपये रह गया। इसकी मुख्य वजह इन राज्यों के पूंजीगत खर्च में गिरावट है। एजेंसी के मुताबिक राज्यों का राजस्व भी गिरा है। इसकी मुख्य वजह गैर-कर राजस्व में कमी, कर राजस्व में विकास की धीमी दर तथा कुछ अन्य कारण हैं। जहां तक खर्च घटने का सवाल है, तो एजेंसी ने कहा है कि इनमें से कई राज्यों में श्रम कानूनों में सुधार नहीं हुए और वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। इसके अलावा कृषि कर्ज के मद में भुगतान और नई योजनाओं के अटकने से भी राज्यों के खर्च में कमी आई। हालांकि सीएजी के प्रारंभिक आंक?ों के आधार पर एजेंसी का यह भी अनुमान है कि इन 13 राज्यों का कुल कर-राजस्व इस वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष के दौरान सुधरकर 10.1 फीसद रहेगा, जो उससे पिछले वित्त वर्ष के आखिर में 7.7 फीसद था। एजेंसी ने यह भी कहा है कि ई-वे बिल के राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन शुरू होने के बाद राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में सुधार होने की पूरी उम्मीद है।

भुगतान में देरी करने पर बीमा कंपनियों को भरना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली ● एजेंसी

भारत सरकार ने उन बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) के तहत किए गए दावों में अस्पतालों को समय से भुगतान नहीं करती हैं। इस योजना के तहत अगर कोई बीमा कंपनी दावे का भुगतान अदा करने में 15 दिन से ज्यादा की देरी करती है, तो उसे दावा राशि पर तब तक एक फीसदी ब्याज देना होगा जब तक वह पूरी तरह भुगतान अदा नहीं कर देती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को जारी एक दस्तावेज के अनुसार बीमा कंपनी सीधे संबंधित अस्पताल को जुर्माना राशि अदा करेगी। इस दस्तावेज में इस योजना के तहत कवर होने वाली राशि और प्रक्रिया की सूची है। अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएचपीएस लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एमओयू (ज्ञापन पत्र) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसका लक्ष्य कमजोर तबके के 10 करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये तक का कवर मुहैया कराना है। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने अब तक इस योजना को अपनाने पर कोई सरकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। हालांकि, इन राज्यों में भी इस योजना को लागू करने पर बातचीत चल रही है। ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त को करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा था कि यह पहल दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थकेयर कार्यक्रम बन जाएगा क्योंकि दुनिया में आबादी के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है और यह कार्यक्रम भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल देगा। केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना का लक्ष्य गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की व्यवसायिक श्रेणी के लोगों को लाभ देना है।

मंडी भाव

उपज का नाम	न्यूनतम	उच्चतम	मंडी
गेहूं लोकवन	1420	2136	20
गेहूं सुजाता	1531	2690	15
गेहूं सामान्य	1500	1670	10
धान (बेहतर)	1800	2580	2
धान (मध्यम)	1325	1826	3
ज्वार	1088	1625	2
मक्का	900	1333	13
तुअर	2000	4076	12
चना देशी	2000	4010	33
चना गुलाबी	2000	5150	7
सोयाबीन पीला	1200	5560	30
सरसों	2500	3915	26
अलसी	3370	3876	5
मूंगफल्ली	3545	3545	1
टमाटर देशी	400	1000	2
आलू देशी	500	1100	2
हरी मिर्च	740	2100	2
प्याज	100	1080	4
केला	500	1100	1
लाल मिर्च	3540	10440	2
धनिया (सूखा)	3000	7000	7
लहसून	500	2300	1
अदरक	100	2680	2
कपास	4987	5564	1

52 हफ्तों के लो पर पहुंचे ये स्टॉक

नई दिल्ली ● एजेंसी

पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव के दौरान कई स्टॉक अपने 52 हफ्तों के निचले स्तर पर या उसके करीब पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स इनमें से कुछ कंपनियों के फंडामेंटल आगे के लिए बेहतर देख रहे हैं। उनका कहना है कि इनमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जिनके स्टॉक में किसी न किसी इश्यू की वजह से गिरावट रही, लेकिन इश्यू खत्म होने के साथ आगे शेयरों में अच्छी तेजी बन सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए मंहगे शेयरों से दूर रहकर ऐसी चुनिंदा कंपनियों के स्टॉक में गिरावट पर बेहतर मौके बने हैं। निवेशक यूपीएल, एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा पावर में आगे बेहतर रिटर्न पा सकते हैं।

सतर्क रहें निवेशक : एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन के दौरान घरेलू स्तर पर कोई मजबूत मार्केट सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। इस दौरान बाजार की चाल घरेलू की बजाए ग्लोबल सेंटीमेंट पर निर्भर होगी। घरेलू स्तर पर मानसून की प्रोग्रेस एक फैक्टर है, लेकिन अगले कुछ सेशन में ग्लोबल ट्रेड वार, क्रूड व रुपए की कीमत, 22 जून को ओपेक देशों की मीटिंग अभी अहम फैक्टर है। ऐसे में बिकवाली का डर है, जिससे निवेशकों को स्टेबिलिटी आने तक महंगे शेयरों से दूर रहना चाहिए। एपिक रिसर्च के सीईओ नदीम मुस्तफा का कहना है कि अर्निंग सीजन, मानसून का अनुमान, जीडीपी डाटा और आरबीआई पॉलिसी के बाद अब घरेलू स्तर पर फिलहाल कोई सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिन ग्लोबल सेंटीमेंट मसलन ट्रेड वार, क्रूड, रुपए की चाल मार्केट के लिए अहम होंगे।

यूपीएल: यूपीएल भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एग्रोकेमिकल कंपनी है, जो एग्रोकेमिकल के रिसर्च, प्रोडक्शन, अनुसंधान, उत्पादन, मार्केटिंग, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर मानसून रहने से कंपनी को फायदा होगा। ब्रोकरेज हाउस केआर चौकसे ने स्टॉक के लिए 998 रुपए का लक्ष्य रखा है। करंट प्राइस 698 रुपए के लिहाज से स्टॉक में 43 फीसदी रिटर्न मिल सकता है।

एनटीपीसी: एनटीपीसी लिमिटेड पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन और एलाइड एक्टिविटीज बिजनेस में है। कंपनी की बैलेंसशीट बेहतर है और कैश की कमी नहीं है। थर्मल पावर में कुल नेशनल कैपेसिटी में करीब 16 फीसदी कैपेसिटी कंपनी के पास है। पिछले 5 साल में कंपनी ने औसतन 2.5 फीसदी की दर से डिविडेंड यील्ड दे रही है। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक में 220 रुपए का लक्ष्य दिया हे।

भारत 1600 करोड़ और चीन 50 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर लगाएगा शुल्क

नई दिल्ली ● एजेंसी

व्यापार के अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे अमेरिका को चीन, यूरोपीय देशों के साथ भारत ने कड़ा जवाब दिया है। अमेरिका के स्टील और एल्युमिनियम पर सीमा शुल्क बढ़ाए जाने के जवाब में भारत ने 24 करोड़ डॉलर (1600 करोड़ रुपये) के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की तैयारी की है।

भारत इसके तहत 30 अमेरिकी उत्पादों को शुल्क के दायरे में लाएगा। इसमें बादाम, सेब, फास्फोरिक एसिड और 800 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिल शामिल हैं। भारत ने 18 मई को डब्ल्यूटीओ को अमेरिका से आयातित 20 उत्पादों की सूची सौंपी थी, जिन पर वह सीमा शुल्क लगाना चाहता है। संशोधित सूची में भारत ने बादाम और हार्ले डेविडसन जैसी बड़े इंजन वाली बाइकों पर प्रस्तावित शुल्क घटाया है। अमेरिका के एकतरफा फैसलों के खिलाफ भारत के अलावा चीन और यूरोपीय संघ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। भारत ने अमेरिकी सरकार से स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए शुल्क से छूट देने की मांग की थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने इसे नहीं माना। भारत ने अमेरिका को इस मामले में डब्ल्यूटीओ में घसीटा है। गौरतलब है कि दो दिन की अमेरिकी यात्रा से लौटे वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने शुक्रवार को कहा था कि भारत व्यापारिक विवादों का हल चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि मार्क लिंसकॉट जून के आखिरी में भारत यात्रा करने वाले हैं। भारत फिलहाल शून्य या नगण्य शुल्क पर 5.6 अरब डॉलर के 3500 उत्पादों का अमेरिका को निर्यात करता है।

यूरोपीय देशों ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाया: यूरोपीय संघ के देशों ने गुरुवार को व्हिस्की, ब्लू जींस, मोटरसाइकिल जैसे अमेरिकी आयातित सामानों पर आयात शुल्क लगाने को मंजूरी दी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील पर 25 फीसदी और एल्युमिनियम पर 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने की प्रतिक्रिया है।

चीन का भी पलटवार, 50 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क

बीजिंग। चीन ने भी पलटवार करते हुए 50 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। अमेरिका ने शुक्रवार को ही 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था। चीन की सरकार ने 50 अरब डॉलर के 659 अमेरिकी उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया है। इसने कहा कि सरकार ने उन उत्पादों की सूची भी जारी की है जिनपर ये अतिरिक्त शुल्क लगेंगे। चीन के सीमा शुल्क आयोग ने कहा कि 34 अरब डॉलर के 545 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क छह जुलाई से प्रभावी होंगे। इनमें कृषि उत्पाद व वाहन आदि शामिल हैं। शेष 114 उत्पादों जिनमें रासायनिक उत्पाद , चिकित्सकीय उपकरण और ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं ।

बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के पास पीएनबी के 15,490 करोड़ रुपए

नई दिल्ली ● एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कहा है कि मई के आखिर तक बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के पास उसकी फंसी रकम का आकार 15,490 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। अप्रैल के मुकाबले यह रकम दो फीसद ज्यादा है। बैंक के मुताबिक इनमें 25 लाख रुपये या उससे ज्यादा कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले विलफुल डिफॉल्टर्स शामिल हैं। इनमें कुदोस केमी, किंगफिशर एयरलाइंस, बीबीएफ इंडस्ट्रीज, आइसीएसए (इंडिया) लिमिटेड, जस इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड, वीएमसी सिस्टम्स, एमबीएस ज्वैलर्स, अरविंद रिमेडीज तथा इंदु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के नाम प्रमुख हैं। इन कंपनियों के पास बैंक का 1,300 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक बकाया है। बैंक के मुताबिक अप्रैल के आखिर में यह आंकड़ा 15,199.57 करोड़ रुपये था। बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर्स के पास 15,171.91 करोड़ रुपए बकाए के साथ बीते वित्त वर्ष की समाप्ति की थी। हीरा कारोबारी नीरव मोदी के हाथों देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का दंश झेल रहे पीएनबी को पिछले वित्त वर्ष में स्टैंडअलोन आधार पर 12,282.82 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा था।

5जी सर्विस जल्द लांच होने की उम्मीद बढ़ी

नई दिल्ली ● एजेंसी

दूरसंचार मंत्रालय द्वारा गठित 5-जी कमेटी ने कहा है कि देश में अगली पीढ़ी की मोबाइल टेलीफोनी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के लिए करीब 6,000 मेगाहर्ट्ज (एमएचजेड) स्पेक्ट्रम फौरन उपलब्ध होने लायक है। कमेटी ने सरकार को अपनी अनुशंसा सौंप दी हैं। अगर अनुशंसा और सुझाव मान लिए जाते हैं, तो देश में बहुत जल्द 5-जी सेवा लांच हो सकती है। इतना ही नहीं, स्पेक्ट्रम की उपलब्ध मात्रा के हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी भी साबित होगी। कमेटी के सदस्य आरोग्यस्वामी पॉलराज ने कहा कि शुरुआत में 5-जी सेवा के जरिये देश में मोबाइल डाटा की स्पीड वर्तमान स्तर से 50 फीसद तक ब?ाई जा सकती है। मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट (एमआइएमओ/मीमो) वायरलेस टेक्नोलॉजी के अग्रणी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर पॉलराज ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) नई सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के क्षेत्र में मजबूत कदम उठा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को 5-जी स्पेक्ट्रम की दरें वाजिब रखनी होंगी, ताकि टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए उन्हें खरीद पाना और जल्द से जल्द सेवा शुरू कर पाना व्यवहार्य हो। गौरतलब है कि मीमो के जरिये वायरलेस सेवा की क्षमता में जबर्दस्त सुधार संभव हो पाया है। वर्तमान में सभी नए वायरलेस सिस्टम में मीमो का उपयोग हो रहा है। दो साल पहले सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत करीब 2,354.55 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बोली लगाई थी। इससे सरकार को साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली थी। वर्तमान में मोबाइल फोन के सिग्नल 800 से 2,600 मेगाहर्ट्ज बैंड के जरिये भेजे जा रहे हैं। कमेटी ने 11 बैंड्स में 5-जी सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान की है। इनमें से प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के अलावा 3.5, 24 और 28 गीगाहर्ट्ज बैंड्स को 5-जी सेवा के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जा सकता है।

बांड में विदेशी निवेश के नियमों में दी राहत

मुंबई ● एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआइ) की ओर से निवेश के नियमों में रियायत देने का फैसला किया है। इससे आरबीआइ ने दोहरे हित साधने का प्रयास किया है। विदेशी निवेश बढ़ने से विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी तो रुपये में गिरावट थामने में मदद मिलेगी, वहीं कर्ज के रूप में बड़ी कंपनियों के बांड में निवेश बढ़ने से कॉरपोरेट बांड की गिरती मांग में सुधार होगा। एफपीआइ को सरकारी बांड, ट्रेजरी बिल, स्टेट डवलपमेंट बांड और कॉरपोरेट बांड जैसे डेट मार्केट के उत्पादों में निवेश की अनुमति दी गई है। हालांकि उन पर कुछ पाबंदियां रहेंगी। सरकारी बांड में अब एफपीआइ निवेश 30 फीसद तक हो सकता है। पहले यह सीमा 20 फीसद थी। एफपीआइ कम से कम तीन साल की परिपक्वता वाले बांड में ही निवेश कर सकेंगे। एफपीआइ के कुल निवेश में लघुकालिक निवेश की हिस्सेदारी 20 फीसद से ज्यादा नहीं हो सकती है। आरबीआइ के अनुसार कॉरपोरेट बांड में एफपीआइ को कम से कम तीन साल के लिए निवेश करने की अनुमति दी गई है।

अहमदाबाद में मेट्रो रेल का काम चल रहा है जिसकी वजह से कई पेड़ काटे जा रहे हैं।

हालांकि फायरिंग में नजीर वोरा का अद्भूत बचाव

कुख्यात नजीर वोरा पर जुहापूरा में दोपहर में फायरिंग से सनसनी

अहमदाबाद । शहर के जुहापूरा क्षेत्र में बागे नीशात सोसाइटी के पास अल अमीन मस्जिद के बाहर रविवार को सुबह में हिस्ट्रिशीटर और कुख्यात नजीर वोरा पर कार में आये तीन शख्सों ने दो राउन्ड फायरिंग करने पर पूरे क्षेत्र में भारी सनसनी मच गई थी । हालांकि अचानक हुए फायरिंग में नजीर वोरा बच गया था । वर्ना कार में आये तीन शख्सों ने नजीर वोरा पर दो राउन्ड फायरिंग करके कार में फरार हो गये थे । इस घटना के मामले में नजीर वोरा ने वेजलपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है । रमजान ईद के दूसरे दिन सुबह में नजीर वोरा पर इस प्रकार से अचानक फायरिंग करने की घटना की वजह से आरोपियों ने प्लानिंग के साथ हमले को अंजाम दिए होने की चर्चा हो रही है । नजीर वोरा पर फायरिंग करने की घटना सामने आने पर पुलिस भी सक्रिय हो गई थी और पूरे मामले में गहन जांच शुरू कर दी है । बिल्डर कम हिस्ट्रिशीटर नजीर वोरा अहमदाबाद में पिछले कई दिनों से जमीन और धमकी देने की प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है । इसके विरूद्ध कई अपराध दर्ज किए गए हैं । जुहापूरा क्षेत्र में बागे नीशात सोसाइटी के पास अल अमीन मस्जिद के बाहर नजीर वोरा रविवार को सुबह में नमाज अदा करने के बाद अपनी सुजूकी एक्सेस स्कूटर पर घर वापस आ रहा था तब कार में आये तीन शख्सों द्वारा इस पर अचानक फायरिंग कर दी । हालांकि इस फायरिंग में नजीर वोरा का अद्भूत बचाव हुआ था । वोरा के बच जाने पर कार में आये हमलावर शख्स तुरंत ही वहां से स्पीड से कार चलाकर फरार हो गये थे ।

गुजरात समेत सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय कृषि और मनरेगा समिति गठित

नीति आयोग की चौथी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में निर्णय

अहमदाबाद (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुलाई गई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि क्षेत्र में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के विनियोग की सिफारिशों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राष्ट्रीय कृषि और मनरेगा समिति गठित की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विजय रूपाणी (गुजरात), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश), नीतीश कुमार (बिहार) और एन. चंद्राबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश) तथा पवन चामलिंग (सिक्किम) का समावेश किया गया है। यह समिति कृषि क्षेत्र में बुआई से पूर्व और कटाई के बाद, दोनों ही अवधि में मनरेगा के माध्यम से कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों के जरिए किसानों की आय में वृद्धि की संभावनाओं की जांच-पड़ताल कर उसके अमल को लेकर सिफारिश देगी। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें गुजरात ने मनरेगा का नवोन्मेषी उपयोग कर प्रशंसनीय काम शुरू किया है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात में हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल अभियान में मनरेगा का नवाचारी प्रयोग कर तालाबों को गहरा करने, नदियों को पुनर्जीवित करने और नहरों की सफाई का कार्य किया गया था। इस अभियान के कारण राज्य में 32 नदियां पुनर्जीवित हुई हैं, 13 हजार से अधिक तालाब गहरे हुए हैं और 5 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की नहरों की सफाई के साथ ही बरसाती पानी की संग्रह क्षमता में 12000 लाख घनफुट से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, इस अभियान के जरिए ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बड़े पैमान पर मुहैया कराए गए हैं। गुजरात के इस महत्वपूर्ण अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। इस तरह, वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का प्रधानमंत्री का ध्येय कृषि क्षेत्र में मनरेगा के नवोन्मेषी संयोजन और उपयोग से साकार करने को गुजरात प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोमवार को गांधीनगर में डॉ. अंबेडकर अंत्योदय विकास निगम (अ.जा.) के नए कार्यालय का कार्यारंभ उप मुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल की उपस्थिति में कराया।

जिला व तहसील पंचायतों में सत्ता बरकरार रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती

अहमदाबाद (ईएमएस)। राज्य की विभिन्न जिला और तहसील पंचायतों में सत्ता में बरकरार रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जिला और तहसील पंचायतों को बचाने के लिए कांग्रेस ने ज्यादातर सदस्यों को गुजरात के बाहर भेज दिया है। जिसमें पाटण जिला पंचायत के सदस्यों को राजस्थान, सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत के सदस्यों को दीव दमण, अहमदाबाद के 1। सद्स्यों को राजस्थान, राजकोट और मोरबी जिला पंचायत के सदस्यों को भी अज्ञात स्थलों पर भेज दिया होने की जानकारी है। पाटण जिले की सांतलपुर, राधनपुर और हारिज तहसील पंचायतों के सदस्यों को भी राजस्थान भेजा गया है। गौरतलब है पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने विधायकों को कर्नाटक के बेंगालूरू स्थित रिसोर्ट में भेज दिया था। उसी तर्ज पर अब राज्य की जिला व तहसील पंचायतों में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए ज्यादातर सदस्यों को गुजरात से बाहर भेज दिया है। कांग्रेस को डर है कि कई तहसील पंचायतों में पार्टी सदस्य बगावत कर सकते हैं और कुछ सदस्य भाजपा के इशारे पर क्रोस वोटिंग कर सकते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए कांग्रेस के महासचिव ने मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 19 और 20 जून होने वाले जिला व तहसील पंचायत के चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर जिला और तहसील पंचायतों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने पूरी चुनावी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है।

जिगिशा सेठ बनी वडोदरा की नई महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष केतन ब्रह्मभट्

वडोदरा (ईएमएस)। वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारियों की प्रथम ढाई साल की अवधि पूर्ण होने पर नए महापौर और उप महापौर के चुनाव हुए। जिसमें जिगिशा सेठ को वडोदरा का नया महापौर नियुक्त किया गया। जबकि उप महापौर डॉ. जीवराज चौहाण को बनाया गया है। सत्येन्द्र पटेल को स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। महानगर पालिका में पार्टी का नेता केतन ब्रह्मभट्ट को और अल्पेश लिंबाचिया को दंडक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है महानगर पालिका के पदाधिकारियों की अवधि ढाई साल की होती है, जिसके पूर्ण होते ही नए पदाधिकारियों को अवसर दिया जाता है। इसी के अंतर्गत अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, भावनगर और जामनगर के बाद वडोदरा महानगर पालिका को महापौर समेत नए पदाधिकारी मिल गए हैं।

13 साल बाद पकड़े गए हत्या के तीन आरोपी, 2 शख्स अब भी फरार

सूरत (ईएमएस)। शहर के रांदेर क्षेत्र में 13 साल पहले एक ऑट रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई थी। हत्या के 13 साल बाद आखिर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आश्चर्य की बात तीनों आरोपी सूरत में रहते होने के बावजूद पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करने में 13 साल लग गए।

जानकारी के मुताबिक सूरत के रांदेर क्षेत्र के नवा रोड पर 26 जनवरी 2005 को पांच शख्सों ने एक ऑटो रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई थी। तीन बाद ऑटो रिक्शा चालक की शिनाख्त में पता चला कि वह सूरत के मेनानगर झुग्गी बस्ती में रहनेवाला अशरफखान कादरखान पठान था। पुलिस के लिए हत्या किसने और क्यों की? इसकी गुत्थी सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं थी। कई बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इस बीच क्राइम ब्रांच ने पूर्व सूचना के आधार पर 36 वर्षीय सुखदेव एकनाथ सैंदाणे, 3। वर्षीय किरण प्रकाशभाई पटेल और 33 वर्षीय जितु उर्फ कालू नारायणभाई राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों शख्स अशरफखान पठान की हत्या के बाद सूरत शहर में ही रह रहे थे।

क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक मृतक अशरफ पठान ने राजू नेपाली से रुपए थे और इन्हीं रुपयों को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। जिसके बाद राजू नेपाली ने सुखदेव सैंदाणे, किरण पटेल और जितु राठौड़ के अलावा पिन्टू उर्फ भास्कर वेडु जादव के साथ मिलकर अशरफखान को सबक सिखाने का फैसला किया था। लेकिन अशरफखान का आक्रामक रूप देख पांचों शख्सों ने मिलकर तीक्ष्ण हथियारों से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले के अन्य दो आरोपी राजू नेपाली और पिन्टू उर्फ भास्कर जादव की पुलिस को तलाश है।

सद्भावना आवास में यूपी-बिहार जैसे दृश्य खड़े हो गए

वटवा में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करके आतंक मचाया

अहमदाबाद । शहर के वटवा क्षेत्र में अपराधी बेखौफ हो गए है । असामाजिक तत्वों ने वटवा के सद्भावना आवास में शनिवार शाम को बाइक धीरे चलाने का पड़ोसी ने कहने पर १० असामाजिक तत्वों ने डंडे के द्वारा आवास योजना में तोड़फोड़ करके आतंक मचाया था । जिसकी वजह से क्षेत्र में तोड़फोड़ और मारपीट के यूपी बिहार जैसे दृश्य खड़े हो गए थे । गुजरात की आर्थिक राजधानी के मारपीट के दृश्यों के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर भारी सनसनी मच गई थी । पूरे मामले में वटवा पुलिस ने रायोटींग अपराध दर्ज करके छह असामाजिक तत्वों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है । इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, शहर के वटवा क्षेत्र में स्थित गरीब आवास योजना में रहने पर सलमाबहन की पुत्री और उनका देवर नीचे खेल रहा था । उस दौरान पड़ोसी में रहते लड़के तेजी से बाइक चलाकर आये थे । अब सलमाबहन ने इस शख्सों को बाइक धीरे चलाने को कहा था और इसी तरीके से स्पीड में बाइक चलाओ तो कोई गंभीर दुर्घटना हो और कोई जानहानि हो ऐसी प्रेरणा दी थी, जिसकी वजह से बाइकचालक शख्स नाराज हो गया था और कुछ देर के बाद दस असामाजिक तत्व वहां आ गये थे और प्रेरणा देनेवाले महिला सहित के स्थानीय निवासियों में धमकी देने के उद्देश्य से गरीब आवास योजना में डंडे के द्वारा तोड़फोड़ की थी और पत्थरबाजी की गई थी । असामाजिक तत्वों ने अंधाधुंध और बेखौफ होकर तोड़फोड़ और हमले में सलमाबहन को चोटें आयी थी । असामाजिक तत्वों के आतंक की वजह से पूरे क्षेत्र में भारी सनसनी मच गई थी । विशेष करके स्थानीय निवासियों में डर और दहशत की भावना फैल चुकी थी । बाद में इस घटना के मामले में पुलिस को जानकारी देने पर पुलिस का काफिला घटना स्थल पर पहुंच गया था और १० असामाजिक तत्वों तथा अज्ञात शख्सों के विरूद्ध रायोटींग का अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है ।

नीति आयोग गवर्निंग काउन्सिल की महत्व की बैठक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री विजय रुपाणी विशेष रूप से उपस्थित हुए।

पारसा गांव में दलित युवक का बारात रोकने पर भारी विवाद

दलित युवक को शादी के समय में अपमानित किए जाने पर जिग्नेश मेवाणी ने सरकार पर निशाना साधा

अहमदाबाद । गुजरात में दलित अत्याचार लगातार बढ़ रहा है । हररोज नई-नई घटना सामने आ रही है। रविवार को गांधीनगर जिला के माणसा तहसील के पारसा गांव में दलित युवक का बारात रोकने का और एक घटना सामने आने पर राज्यभर में भारी सनसनी मच गई है । विशेष करके दलित समाज में भारी नाराजगी की भावना फैल चुकी है । दलित युवक का बारात रोकने पर स्थानीय पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो गई थी और पुलिस ने बंदोबस्त के साथ युवक की शादी को पूरा कराया था और कोई घटना नहीं हो इस उद्देश्य से गांव में अतिरिक्त पुलिस का बंदोबस्त तैनात किया गया था । दूसरी तरफ, दलित युवा नेता और वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी ने इस घटना को लेकर फिर एकबार भाजपा सरकार पर निशाना साधा था और ट्वीट करके इसे सरकार की साजिश बतायी है । गांधीनगर जिला के माणसा तहसील के पारसा गांव में रविवार को एक दलित युवक की बारात निकली थी । घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर निकले युवक को गांव के दरबार समाज के लोगों ने घोड़ी पर से उतारकर अपमानित किया था । इसके साथ-साथ पूरा बारात रोकने पर एक समय तो माहौल तनावपूर्ण हो गया था और घटना की जानकारी मिलने पर सनसनी मच गई थी । जिसकी वजह से पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई थी और दोनों पक्षों को समझाकर परिस्थिति को शांत कराया था । पुलिस ने पर्याप्त बंदोबस्त के बीच युवक की शादी को संपन्न करवाया था । हालांकि इस घटना को लेकर पूरे राज्य में दलित समाज में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है । दलित युवा नेता और विधायक जिग्नेश मेवाणी ने तो इस घटना को लेकर फिर से सरकार पर निशाना साधा है ।

हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच द्वारा डी.आर. वर्ड पर्वत पाटिया में किया गया।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com